Sl. No.	States/UTs	Robbery in Running Trains	Name of the place	Name of the Train	No. of Persons Arrested
		(xv)	Between Damdam and Bidhanagar	Dn-Ranaghat Local	0
		(xvi)	Between Shamuktala and Nonai Bridge	DN-5715 Tejpur-S. Pur	1
		(xvii)	Kharagpur PF No. 3	UP-Gumo Passenger	0
	TOTAL	58			43

N.B. 1. There are no Railways in A and N Islands, Arunachal Pradesh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep, Meghalaya and Sikkim.

2. Details have not been received from Bihar, Delhi and Maharashtra.

3. NA Stands for not applicable.

दिल्ली पुलिस के थानाध्यक्ष

1597. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस के उन थानाध्यक्षों का ब्यौरा क्या है जो लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से विभिन्न थानों में थानाध्यक्ष रहे हैं;

(ख) थानाध्यक्ष स्तर के उन कर्मियों का ब्यौरा क्या है जो कभी भी थानाध्यक्ष नहीं रहे; और

(ग) पांच वर्षों से अधिक समय तक एक स्थान पर थानाध्यक्ष रहे कर्मियों को स्थानान्तरित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) इस समय केवल एक निरीक्षक (कार्यकारी) ही ऐसा है जो पांच वर्ष से अधिक समय तक थाना प्रभारी के रूप में लगातार तैनात रहा हो।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस में ऐसे 453 निरीक्षक (कार्यकारी) हैं, जिन्हें थाना प्रभारी के रूप में कार्य करने का अब तक एक भी मौका नहीं मिला है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल प्रमाणित योग्यता के अधिकारियों को ही थाने का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा, पुलिस थानों की तुलना में निरीक्षकों (कार्यकारी) की संख्या अधिक होने के कारण, इन सभी को थाना प्रभारी की ड्यूटियां सौंपना संभव नहीं है।

काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में डकैती

1598. **श्री रामजीलाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1999 के राष्ट्रीय सहारा में "काशी विश्वनाथ ट्रेन में 4 लाख की लूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में लूटपाट की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार पीड़ितों को कोई मुआवजा देती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत आठ महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में लूटपाट की कितनी घटनायें हुई हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ग) चलती रेलों में हुए अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस (जी॰आर॰पी॰) की जिम्मेदारी है, जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य करती है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों को रेल यात्राओं के दौरान यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह देती आई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, जी॰आर॰पी॰ और रेलवे सुरक्षा बल (आर॰पी॰एफ॰) के बीच नियमित रूप से बैठकें करने की जरूरत, चलती रेलों में चल-पुलिस बल तैनात करना, पुलिस एस्कोर्ट और रेलवे स्टाफ के बीच तालमेल में सुधार लाना, अनधिकृत फेरी वालों, शरारती तत्वों तथा अन्य आवंछित तत्वों आदि को हटाना शामिल है।

रेलवे द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है जो रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं/घायल होते है।

(घ) पिछले 8 माह के दौरान (मई, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक) चलती रेलों में हुई लूटपाट/डकैती की घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले 8 माह (मई 98 से दिसम्बर 98 तक) के दौरान चलती रेलों में हुई लूटपाट/डकैती की घटनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चलती रेलों में लूटपाट	चलती रेलों में डकैती
आन्ध्र प्रदेश	4	1
अ. और न. द्वीपसमूह	कोई रेलवे नहीं	
अरूणाचल प्रदेश	कोई रेलवे नहीं	
असम	10	6
बिहार	प्राप्त नहीं हुई	
चंडीगढ़	0	0
दमन और द्वीप	कोई रेलवे नहीं	
दा. और न. हवेली	कोई रेलवे नहीं	
दिल्ली	प्राप्त नहीं हुई	
गोवा	0	0
गुजरात	19	2
हरियाणा	0	1
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
कर्नाटक	0	0
केरल	0	0
लक्ष्यद्वीप	कोई रेलवे नहीं	
महाराष्ट्र	17	9
मध्य प्रदेश	17	0
मेघालय	कोई रेलवे नहीं	
मिजोरम	0	0
मणिपुर	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	7	0
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	0	0
राजस्थान	10	0
सिक्किम	कोई रेलवे नहीं	
तमिलनाडु	6	0
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	27	7
पश्चिम बंगाल	28	16
कुल	145	42

कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति में बिहार पुलिस की भागीदारी

1599. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बिहार की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए बिना पुलिस काफी हद तक जिम्मेदार है; और क्या यह निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फसाने और उन्हें आकारण उत्पीड़ित करने की आदी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को नालंदा थाने, जिला नालंदा (बिहार) के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 20 अगस्त, 1998 के "आज" से "नालन्दा के पुलिस अधिकारी की धांधली की सुनवाई अदालत में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Separate Human Rights Commission for the North-East

1600. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has been demanded that a separate Human Rights Commission for North-Eastern Region should be set up; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The Central Government has been pursuing the matter of setting up State Human Rights Commissions with the State Governments. In response to this,